

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 144]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 25, 1974/चैत्र 4, 1896

No. 144]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 25, 1974/CHAITRA 4, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF LABOUR

### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March 1974

S.O. 206(E).—Whereas the Central Government is of opinion that any employment under the Hindustan Construction Company Limited in the Haldia Dock Project (hereinafter referred to as the said employment) is essential for maintaining supplies and services essential to the life of the community;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 119 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby declares the said employment to be an employment to which rule 119 of the said rules applies.

[No. F. S-42025/5/74/II-LR.I]

अम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1974

क्रा० प्रा० 206(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि हाल्डिया डोक परियोजना में हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के अधीन कोई नियोजन (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियोजन कहा गया है), समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाये रखने के लिये आवश्यक है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 119 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियोजन को ऐसे नियोजन के रूप में घोषित करती है, जिसे उक्त नियमों का नियम 119 लागू होता है।

[सं० फा० एस०-42025/5/74/II-एल० आर० 1]

#### ORDER

*New Delhi, the 25th March 1974*

**S.O. 207(E).**—Whereas the Central Government have, by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S-42025/5/74-LR.I, dated the 25th March, 1974, declared employment under the Hindustan Construction Company Limited in the Haldia Dock Project to be an employment to which rule 119 of the Defence of India Rules, 1971, applies;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 119 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby regulates the wages in respect of persons who are workmen as defined in clause (s) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) and are employed in such employment in the manner specified in the Schedule annexed hereto.

#### SCHEDULE

The existing wages of all categories of workmen shall be increased by Rs. 15 per head per month;

Provided that this increase shall not count towards any other benefit, statutory or otherwise, and subject to subsequent adjustment in terms of the award of the National Industrial Tribunal set up by the order of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2193 dated the 1st December, 1973 in the industrial dispute referred to that Tribunal by the said order.

[No. F. S-42025/5/74/II-LR.I]

N. P. DUBE, Addl. Secy.

नई दिल्ली, 25 मार्च 1974

#### आदेश

**फा० आ० 207(अ).**—यतः केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम मंत्रालय का अधिसूचना सं० एस-42025/5/74-एल आर 1 तारीख 25 मार्च, 1974 द्वारा, हाल्डिया डॉक परियोजना में हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के श्रमिक नियोजन को ऐसे नियोजन के रूप में घोषित किया है जिसे भारत रक्षा नियम, 1971 का नियम 119 लागू होता है;

अतः, अब भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 119 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उन व्यक्तियों की बाबत, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 47 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (क) में यथा परिभाषित कर्मकार हैं और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से ऐसे नियोजन में लगे हुए हैं, मजदूरी विनियमित करती है।

#### अनुसूची

“सभी प्रवर्गों के कर्मकारों की विद्यमान मजदूरी में प्रतिमास प्रति व्यक्ति 15 रु० की वृद्धि की जाएगी :

परन्तु यह वृद्धि किसी अन्य फायदे कानूनी या अन्यथा, में नहीं गिनी जाएगी और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 3493 तारीख 1 दिसम्बर, 1973 द्वारा गठित राष्ट्रीय औद्योगिक प्रतिकरण के उक्त आदेश द्वारा उस अधिकरण को निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, पंचाट के अनुसार पश्चात्तवर्ती करार के अधीन होगी। ”

[सं० फा० एस-42025/5/74 II-एल आर 1]

एन० पी० दूवे, अपर सचिव।

